

क्रमांक 365/मु.स./2000

भोपाल, दिनांक-22 अगस्त, 2000

प्रति,

समस्त फ्लोवटर,  
मध्य प्रदेश.

विषय:- वन क्षेत्रों में अवैध कटई एवं अतिक्रमण की रोकथाम।

...

प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा वनों से आच्छादित है, जो पूरे देश के वन क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत है। विगत कुछ वर्षों के प्रयासों से प्रदेश के वन क्षेत्र में लगभग 635 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है, किन्तु अभी भी लगभग 60 लाख हेक्टर क्षेत्र बिगड़े वनों की श्रेणी में है। वनों के संरक्षण एवं बिगड़े वनों के सुधार के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि मध्यप्रदेश, हरित प्रदेश के नाम से जाना जाए।

वनों के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि वन क्षेत्रों में अतिक्रमण नहीं होने पाये तथा अतिक्रमणकर्ताओं को वेदखत किया जाए। ऐसी अपेक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका क्रमांक 202/95 टी. गोदावर्मेन विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में दायर विभिन्न अन्तरिम याचिकाओं एवं जवाबवाचों में राज्य शासन से की जाती है।

इस दिशा में फ्लोवटर स्तर से निम्नलिखित कार्यवाही की जाए:-

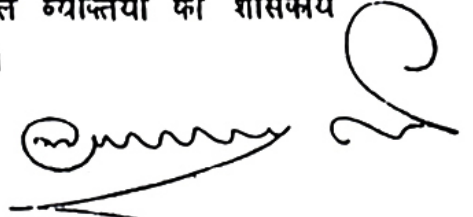
11 फ्लोवटर की अध्यक्षता में एक टस्कफोर्स का गठन किया जाए, जिसमें जिले के पुलिस अधीक्षक एवं वन मण्डलाधिकारी को सम्मिलित किया जाए। यह समिति वन क्षेत्रों में अवैध कटई एवं अतिक्रमण के मामलों की प्रतीगाह सगीषा फरेगी तथा अतिक्रमणों एवं अवैध कटई के प्रयासों को रोकने के लिए कार्य-योजना तैयार कर समन्वित प्रयासों से उसका क्रियान्वयन करेगी।

12 प्रदेश में वन समितियों के माध्यम से जन भागीदारी प्रोत्साहित की गई है। इन समितियों को और अधिक जागरूक एवं सुदृढ़ बनाया जाए, ताकि इनके

सदयोग से यन भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को वहां से हटाकर उन्हें अन्य रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

। 3। सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे जब भी भ्रमण पर जाएं, तब वे स्थानीय लोगों को वनों के महत्व एवं वनों के संरक्षण के सम्बन्ध में समझाएँ, ताकि यन संरक्षण की दिशा में वे जागरूक होकर सार्थक पदत कर सकें।

। 4। वनों में अथेय कर्तृ एवं अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को शासकीय अनुबान/सहायता देने में हतोत्साहित किया जाए।



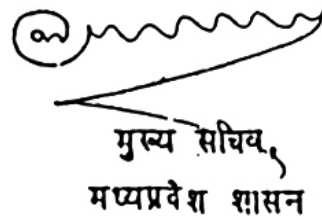
। के.एस.शर्मा।  
मुख्य सचिव  
मध्य प्रदेश शासन

पृष्ठांक. 366 /मुस/2000

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त, 2000

प्रतिनिधि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, यन विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल.
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल.
3. समस्त कमीशनर, मध्यप्रदेश.



मुख्य सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन